should have become bogged down in petty intrigues and administrative bungling. I would urge that the Government of India should immediately move to take over Aurobille as a national memorial of Sri Aurobindo and for this purpose bring a Bill before the Parliament as early as possible.

(iv) SUPPLY OF ESSENTIAL COMMODITIES AT REASONABLE PRICES.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं । चीनी, दाल, तेल, साबुन एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में पुनः वृद्धि हो गयी है । चीनी का दाम कहीं-कहीं तो आठ रूपए प्रति किलो हो गया है, जिससे गरीब आदमी तो उसे खरीद भी नही सकता । गुड़ की भी कीमत एक माह के भीतर दुगुनी हो गयी है । बेबी-फूड की कीमत प्रायः बढ़ती चली जा रही है । सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति में निहित दोष के कारण बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण नही स्थापित हो पा रहा है । बहुत सी वस्तुयें जैसे सीमेंट आदि तो उपभोक्ताओ को मिल भी नही पा रही है ।

अतः सरकार को शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें जिससे उपभोक्ता वस्तुये सस्ते दामों पर आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें । बजट पेश होने के बाद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि अत्यन्त चिन्ताजनक है । नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को तत्काल इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए ।

(v) NEED TO RESUME RELIEF WORK IN THE TRIBAL AREAS OF JHABUA RATALM, DHAR AND KHARGON DISTRICTS MADHYA PRADESH.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में झाबुआ रतनाम, धार, खरगौन जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में जहां एक ओर अकाल राहत कार्य बन्द कर दिए गए हैं, वहां दूसरी ओर कई महीनों की मजदूरी का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है । साथ ही सस्ते अनाज की दुकानों में आदिवासियों का मुख्य भोजन मोटा अनाज, ज्वार, मक्का आदि उपलब्ध नही हैं । बाजार में ऊंचे दामों में अनाज मिल रहा है, जिसे आदिवासी क्रय नहीं कर सकता है ।

अतः सर्वत्र आदिवासियों में भुखमरी एवं असन्तोष व्याप्त है । राज्य सरकार को निर्देश दिये जाये कि जब तक नई फसल नहीं पके तब तक राहत कार्य जारी रखे जायें एवं मजदूरी का अविलम्ब भुगतान किया जाये और शासकीय सस्ते अनाज की दुकानों पर मोटे अनाज की व्यवस्था की जाये ।

(vi) NEED FOR IMMEDIATE SUPPLY OF WHEAT FOR "FOOD FOR WORK" PROGRAME IN RAJASTHAN.

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जो उनके गोदामों में जमा कर रखा था, उक्त स्टाक प्रान्त में दस दिन से बिल्कुल समाप्त हो गया है । जिसके कारण राजस्थान प्रान्त में जिला बाड़मेर, जैसलमेर, आदि में अकाल राहत कार्य चलते थे, वह बन्द हो गए हैं । अन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रहे थे वे सभी बन्द हो गए हैं सस्ते अनाज की दुकानों में प्रान्त भर में गेहूं के न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असन्तोष है । गेहूं के भाव चरम सीमा पर पहुंच गए हैं । अकाल राहत कार्य एवं अनाज के बदले कार्य, फूड फार वर्क नहीं चलने से कुछ जिलों में भुखमरी की स्थिति आ रही है । अतः केन्द्र सरकार तुरन्त राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जल्दी से जल्दी पहुंचा कर राजस्थान की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करे ।

(vii) REPORTED VIOLATION OF THE COMPANIES ACT, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT, ETC., BY FOREIGN COMPANIES OPERATING IN INDIA.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it has been reported that official inspection has brought out that branches and subsidiaries of Foreign Companies operating in India are violating with impunity the Companies Act, Industrial Development Regulation Act (Licencing), Foreign Exchange Regulation Act and MRTP.

The British companies numbering 319 some time ago were on top of the list in this adventure. Although the number has come down because of FERA compulsion, they have increased the remittances considerably. Their assets are going up by leaps and bounds. In 1973-74, the white money value of their assets was

[Shri Joytirmoy Bosu]

shown as Rs. 1790.4 crores, by 1978-79 it has gone up to Rs. 2401.4 crores. In 1975-76, it was Rs. 2178.2 crores. Besides, there is a huge amount of black money mainly kept with their distributors, agents dealers and benamidars. It is estimated that an amount of Rs. 1500 crores go out of the country through invoice manipulation every year. A big part of this money is given in Indian rupees to the foreign agents and missionaries for anti-India activities in the country.

The Managing Director of a Motor Company, a Britisher who has shifted his activities from Calcutta to Shillong, has given millions of rupees to foreign missionaries in Indian rupees and took back the same in foreign currencies, abroad with a premium.

Detailed reply from the concerned Ministry is called for.

12.52 hrs.

*

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL, 1980-81—*Contd.*

MINISTRY OF INDUSTRY—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Industry.

Mrs. Krishna Sahi.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में जब माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज, भाषण दे रहे थ, तो मैं ने बहुत ध्यान से उसको भी सुना और तीन वर्ष का उनका और उनकी पार्टी का परफामेन्स भी देखा । वह अपने भाषण में अपनी सरकार की नीतियों की दुदुभि भी जोर से बजा रहे थे और अपनी उपलब्धियों की झड़ी भी लगा रहे थे । लेकिन मैं समझती हूं कि उस श्रृंखला में वह कुछ कड़ियों को जोड़ना भूल गये । मैं अपनी ोर से उनकी तथा-कथित सफलताओं को उसमें जोड़ना चाहती हूं ।

मैं जानना चाहती हूं कि जनता पार्टी के शासन-काल के तीन वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों में कितनी हड़तालें हुईं, कितने लाक-आउट्स हुए, हमारे कितने उद्योग-धंधे बन्द हो गये और कितने मैनडेज का लास हुआ । इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन कहां तक पहुंच गया ? गत वर्ष हमारा उत्पादन शून्य तक पहुंच गया, उससे हमारी कितनी राष्ट्रीय क्षति हुई ? ये सारी बातें हमारे सामने प्रश्न-चिन्ह बन कर उपस्थित हैं ।

जनता पार्टी की सरकार तीन वर्षों तक रही और अपने औद्योगिक साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों पर से सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटा लिया । मनोपलीज कमीशन की भूमिका नगण्य रह गई और उसके अधिकार बहुत सीमित हो गए । बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सूद की रियायत मिल गई और उनकी साधन आसानी से उपलब्ध किये गये । कहने का मतलब यह है कि जहां उनके अपने खजाने मोटे हो गये, वहां औद्योगिक क्षमता निम्नतम स्तर पर पहुंच गई ।

देश को आर्थिक स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की ओर ले जाना प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था । उनका दर्शन देश मे औद्योगिक क्रान्ति का अग्रदूत बन कर आया था । जब तक हमारी पार्टी की सरकार रही, तब हम आत्म-निर्भरता की ओर जा रहे थे । लेकिन जब जनता पार्टी का शासन आया, तो इस दर्शन पर कड़ा प्रहार हुआ और इसका सब से बुरा असर औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ा । मैं उसका एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहती हूं । तीन वर्षों में राची के एच ई सी को खोखला बना दिया गया । पता नहीं किस को व्यवस्थापक के रूप में इन्होने भेजा, मैं किसी का नाम नही लेना चाहती, लेकिन जो व्यवस्थापक यहां से गए उन्होने तीन वर्षों में उस को खोखला ही नही बना दिया बल्कि सब तरफ से उस को अपंग बना कर छोड दिया । 77, 78 और 79 तक 65 करोड़ का तो कारखाने का लास हुआ है और इस के अलावा जो उस के एस्टैब्लिशमेंट पर खर्च था वह तो बढ़ता ही चला गया । इसी एच ई सी में 76 और 77 में इस के उत्पादन के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी और मुनाफा भी हुआ था । एच ई सी हिन्दुस्तान की आर्थिक ऊंचाई का एक बहुत बड़ा स्तम्भ है । लेकिन वहां ऐसे व्यवस्थापक गए जो उस की निगरानी तो कुछ कर नहीं सके, उस का उत्पादन कुछ कर नहीं सके उलटे वहां जो उत्पादन हो सकता था और होता था उस को भी बन्द कर दिया । तत्कालीन उद्योग मंत्री ने संभवत: जैसी कि हम लोगों की जानकारी है, वैस्ट जर्मनी की एक

*Moved with the recommendation of the President.